

शिक्षा में कदाचार और अनाचार : भ्रष्टाचार के कुपरिणाम

डॉ० बामेश्वर प्रसाद

व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, पैरू महतो सोमरी महाविद्यालय बिहारषरीफ ,नालंदा, बिहार
(पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना, बिहार भारत)

सार :- हमारे देश में कदाचार और अनाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह हमारे समाज और राष्ट्र के सभी अंगों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रभावित किए जा रहा है। राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, उद्योग, प्रशासन आदि में कदाचार और अनाचार की पैठ आज इतनी अधिक हो चुकी है कि इससे मुक्ति मिलना बहुत कठिन लग रहा है। चारों ओर दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, अनाचार आदि सभी कुछ कदाचार और अनाचार के ही प्रतीक हैं। इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं लेकिन वास्तव में वे सब कदाचार और अनाचार की जड़ें ही हैं। इसलिए कदाचार और अनाचार के कई नाम रूप तो हो गए हैं, लेकिन उनके कार्य और प्रभाव समान हैं या एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं। भ्रष्टाचार के कारण क्या हो सकते हैं। यह सर्वविदित है।

प्रस्तावना :- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आमूल परिवर्तन हेतु सरकार ने 1948-49 में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णण के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया जिसमें कई ठोस सिफारिशें कीं। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बराबर किया गया। वर्ष 1964-66 में डॉ० कोठारी की अध्यक्षता में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया गया। जिसने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सन् 1969 में वि०वि० के लिये मुंबई वि०वि० के तत्कालीन कुलपति डॉ० पी०बी० गजेन्द्र गडकर और अन्य महाविद्यालयों के लिये गोरखपुर वि०वि० के कुलपति डॉ० पी०टी० चांडी की अध्यक्षता में अलग-अलग राष्ट्रीय शिक्षा समितियाँ गठित हुईं जिन्हें बाद में मिलाकर डॉ० एस०एन० सेन की अध्यक्षता में नया शिक्षा आयोग बनाया गया जिसके आधार पर ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नया वेतनमान लागू किया गया तदोपरान्त 1983-85 में उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए डॉ० रईस अहमद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग और वेतन पुनरीक्षण हेतु जयपुर वि०वि० के प्रख्यात रासायनशास्त्री प्रो० आर० सी० मेहरोत्रा की अध्यक्षता में एक अलग आयोग गठित किया गया। जिनकी सिफारिशों के आधार पर जनवरी 1986 से ही सभी शिक्षकों को नया वेतनमान दिया गया है। बिहार में यह कागज पर ही लागू हुआ है।

विवेचन :- रईस अहमद राष्ट्रीय शिक्षण आयोग-2 की रिपोर्ट के अनुसार, "बहुव्यापी अनभूति है कि जितना हास शिक्षण व्यवसाय की प्रतिष्ठा का हुआ है, किसी अन्य व्यवसाय का नहीं। यह सत्य है कि वर्तमान स्थिति अति असंतोषप्रद है। जिसके लिये तुरंत उपचार किये जाने चाहिए। इसी प्रकार यूनेस्को के सातवे दशक में अंतर सरकार सम्मेलन में भी यह सिफारिश की गयी। शिक्षकों के कार्य की स्थितियाँ, उन्हें दिये जाने वाले वेतन तथा अन्य जीवन सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। आयोग की यह भी धारणा है कि समाज में एक शिक्षण को जितनी मान्यता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है।

आज बिहार के सारे संस्थान रोगग्रसिता है। प्रश्न उठता है, इतनी जर्जरता के आखिर कारण क्या है ? मेरी यह मानता है कि इसके अनेक कारण हैं किंतु इसके लिय शिक्षक, छात्र, अभिभावक, वि०वि० पदाधिकारी, राजनेता और सरकार सभी जबाबदेह हैं। किन्हीं एक को पूरी तरह जबाबदेह ठहराना घोर अन्याय और एकपक्षीय होगा। फिर भी सरकार एवं राजनेताओं का दोष सर्वाधिक है।

रईस अहमद आयोग 1985 ने भी अपने द्वितीय रिपोर्ट में यह शिकायत कि है कि "अधिकांश शिक्षक पूरी दक्षिता और प्रतिभा रखते हुये भी अपने कार्य और दायित्व से कतराते है। पठन-पाठन में निरसता प्रदर्शित करते है। कई ऐसे है जो कम मेधावी है और प्रतिभाओं को दमित कर पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने में सफल हो गये है। प्राइवेट ट्यूशन को प्रोत्साहित करते है और उसी मे रमे रहते है जिससे शिक्षको कि सामाजिक प्रतिष्ठा में आँच आई है। छात्रों के दिल ने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा में कमी आई है। बिहार में तो यह सामान्य बात होती जा रही है। कई ऐसे लोग भी है जो अपना निजी हित साधने के लिए अनुशासन हीन छात्रों एवं समाज विरोधी तत्वों का सहारा लें उन्हे संरक्षण दें। परिसर मे अशांति कराते है। संस्थान और अपने पद की गरिमा का तनिक भी ख्याल नहीं करते, जो सचमुच भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र भी इस खराब स्थिति के लिए कम जबावदेह नहीं है। यहाँ बहुतायत छात्र पठन-पाठन में अपेक्षाकृत कम ध्यान देते है। या तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते या फिर लगाते भी है तो काफीकम कई प्रकार कि गलत और बुरी आदते पकड़ते जाते है। बिना परिश्रम के ही कदाचार पूर्ण परीक्षा के माध्यम से सर्वाधिक अंको से उतीर्ण होना चाहते है। दुर्भाग्यवश कतिपय शिक्षकों की भी इसमें भागीदारी रहती है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण प्रतिभापलायन तेजी से हो रहा है। जिससे भावी पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है जो बिहार के लिए घातक है। अभिभावकों कि भी इसमें कम भूमिका नहीं रहती है। ऐसे अभिभावको की आज संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जा अपने बच्चों को येन केन प्रकारेण उँची-उँची उपाधिया और सर्वाधिक अंक दिलाना चाहते है। छात्र से अभिभावक ही ज्यादा सक्रियता और उत्साह प्रदर्शित करते है।

अन्त में, सर्वाधिक दोषी सरकार है। सेन आयोग कि तरह ही रईस अहमद आयोग ने यह स्वीकार किया है कि राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों कि उपेक्षा कि स्थिति में गिरावट आयी है। शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने, वि०वि० एवं महाविद्यालयों के दैनिक कार्यों में बढ़ रहे राजनीतिक हस्तक्षेप, और उनकी स्वायतता पर किये जा रहे नियमित कुठारावात के प्रति इन राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों ने काफी चिंता व्यक्त कि है। आज बिहार की सभी संस्थानों कि बदहाली और उच्च शिक्षा में गुणात्मक हास दोनों के लिए सरकार अधिक दोषी है। आज सभी शिक्षको एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए मुहताज रहना पड़ रहा है। अन्य सुविधाओं कि तो बात ही अलग है। वित्तीय अनुशासन के नाम पर वि० वि० के बजट को बेरहमी से काट लिया जाता है। स्वीकृत राशि से भी कम और वह भी अनियमित रूप से सरकार द्वारा विमुक्त कि जाती है। यह उपेक्षात्मक प्रवृत्ति विगत वर्षों में तीव्रतर ही होती जा रही है, जो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और विभेदात्मक है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को अनुत्पादक समझा जाना लगा है। आश्चर्य होता है कि इस नासमझी पर सरकार यह भूल जाती है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों कि कितनी बड़ी भूमिका होती है। यह खेद जनक है कि देश के राजनीतिज्ञों एवं सरकार के विभिन्न शिक्षकेत्तर सरकारी विभागों (यथा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वित्त, कल्याण, कृषि, सिंचाई, उद्योग, लोकनिर्माण विभाग आदि) में कुट-कुट कर व्याप्त भ्रष्टाचार नजर नहीं आते किन्तु कितनी विचित्र बात है कि इन शैक्षणिक संस्थानो में कार्यरत लोगों को समय पर पुरा वेतन भी नहीं मिले, छात्रों को पुस्तके और प्रयोगशाला उपकरण न उपलब्ध हो। क्या यही दिन देखने के लिए भारत में "कल्याणकारी राज्य" और "समाजवादी समाज की स्थापना कि थी आज कि स्थिति तो यह है कि कुलपतियों को भी प्रतिमाह वित्तीय अनुदान के लिए सचिवालय मे चक्कर लगाना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि कुलपति का पद कितना गरिमामय है। किन्तु इस कुव्यवस्था के सामने उन्हे भी घुटने टेकने पड़ते है। इस गरिमा को गिराने में एक मात्र हाथ सरकार और राजनेताओं का है।

शिक्षक संघ और छात्र संगठन भी विभिन्न राजनीतिक दलों में संबद्ध होकर अधिकांश मुद्दो पर शिक्षकों एवं छात्रों के व्यापक हितों को ताक पर रख देते है। प्रायः इनका नेतृत्व भी संकिर्णताओं में बंध जाता है। कदाचार और अनाचार के वातावरण में ईमानदारी और सत्यता तो छूमन्तर की तरह गायब हो जाते हैं।

इनके स्थान पर केवल बेईमानी और कपट का प्रचार और प्रसार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कदाचार और अनाचार का केवल दुष्प्रभाव ही होता है इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती होती है। कदाचार और अनाचार के द्वारा केवल दुष्प्रवृत्तियों और दुष्चरित्रता को ही बढ़ावा मिलता है। इससे सच्चरित्रता और सद्प्रवृत्ति की जड़ें समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है कि कदाचार और अनाचार की राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और धार्मिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो गई हैं कि इन्हें उखाड़ना और इनके स्थान पर साफ सुथरा वातावरण का निर्माण करना आज प्रत्येक राष्ट्र के लिए लोहे के चने चबाने के समान कठिन हो रहा है। कदाचार और अनाचार दो शब्द हैं, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट का अर्थ है- बुरा या बिगड़ा हुआ और आचार का अर्थ है आचरण। कदाचार और अनाचार का शाब्दिक अर्थ हुआ – वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है।

यह सर्वविदित है कि शिक्षा चाहे प्राथमिक हो या उच्चतर व्यवहारिक हो या अध्यात्मिक, औपचारिक हो या अनौपचारिक लोगों में संस्कार गढ़ती है। यह एक जीवन शैली है, जिसके सहारे लोग व्यक्ति बोध तथा सामाजिक दायित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वृहतर परिपेक्ष्य में शिक्षाजीवन जीने के आयाम खोलती है। शिक्षा के इस आयाम पर विचार करने से यह एहसास होता है कि लॉर्ड मेकाले से लेकर स्वतन्त्र भारत में जितनी भी शिक्षा नीतियाँ बनी लोगों को मुक्ति करने के बजाय बंधन युक्त करती रही है। शिक्षा का सीधा संबंध देश एवं समाज की जीवनधारा से होता है। अतः बार-बार शिक्षा के नाम पर किये जा रहे प्रयोग का सीधा प्रहार देश के बच्चों पर पड़ता है जो प्रकारान्तर से राष्ट्रहीन के प्रतिकूल ही होती है वर्तमान नई शिक्षा पद्धति इसी संदर्भ की एक विशेष कड़ी है। यों तो स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास और आमूल सुधार हेतु अनेक प्रयास किये गये। तथापि शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति अधिक शर्मनाक और दुःखद मोड़ पर पहुँचती जा रही है। उसमें भी उच्चतर शिक्षा की स्थिति तो और भी नाजूक होती जा रही है।

निष्कर्ष :- भ्रष्टाचार के कुपरिणामस्वरूप समाज और राष्ट्र में व्यापक रूप से असमानता और अव्यवस्था का उदय होता है। इससे ठीक प्रकार से कोई कार्य पद्धति चल नहीं पाती है और सबके अन्दर भय, आक्रोश और चिंता की लहरें उठने लगती हैं। असामानता का मुख्य प्रभाव यह भी होता है कि यदि एक व्यक्ति या वर्ग बहुत प्रसन्न है, तो दूसरा व्यक्ति या वर्ग बहुत ही निराश और दुखी है। कदाचार और अनाचार के वातावरण में ईमानदारी और सत्यता तो छूमन्तर की तरह गायब हो जाते हैं। इनके स्थान पर केवल बेईमानी और कपट का प्रचार और प्रसार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कदाचार और अनाचार का केवल दुष्प्रभाव ही होता है इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती होती है। कदाचार और अनाचार के द्वारा केवल दुष्प्रवृत्तियों और दुष्चरित्रता को ही बढ़ावा मिलता है। इससे सच्चरित्रता और सद्प्रवृत्ति की जड़ें समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है कि कदाचार और अनाचार की राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और धार्मिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो गई हैं कि इन्हें उखाड़ना और इनके स्थान पर साफ सुथरा वातावरण का निर्माण करना आज प्रत्येक राष्ट्र के लिए लोहे के चने चबाने के समान कठिन हो रहा है। नकली माल बेचना, खरीदना, वस्तुओं में मिलावट करते जाना, धर्म का नाम ले लेकर अधर्म का आश्रय ग्रहण करना, कुर्सीवाद का समर्थन करते हुए इस दल से उस दल में आना जाना, दोषी और अपराधी तत्वों को घूस लेकर छोड़ देना और रिश्वत लेने के लिए निरपराधी तत्वों को गिरफ्तार करना, किसी पद के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करके रिश्वत लेना, पैसे के मोह और आकर्षण के कारण हाथ हत्या, प्रदर्शन, लूट पाट चोरी, कालाबाजारी, तस्करी आदि सब कुछ कदाचार और अनाचार के मुख्य कारण हैं। भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम इसके दोषी तत्वों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दें कि दूसरा भ्रष्टाचारी फिर सिर न उठा सके। इसके लिए सबसे सार्थक और सही कदम होगा। प्रशासन को सख्त और चुस्त बनना होगा। न केवल

सरकार अपितु सभी सामाजिक ओर धार्मिक संस्थाएँ, समाज और राष्ट्र के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ सच्चे सेवकों, मानवता एवं नैतिकता के पुजारियों को प्रोत्साहन और पारितोक्षिक दे देकर भ्रष्टाचारियों के हीन मनोबल को तोड़ना चाहिए। इससे सच्चाई, कर्तव्यपरायणता और कर्मठता की यह दिव्य ज्योति जल सकेगी। जोकदाचार और अनाचार के अंधकार को समाप्त करके सुन्दर प्रकाश करने में समर्थ सिद्ध होगी।

सन्दर्भ पुस्तक

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. हिन्दुस्तान, 22 दिसम्बर 1987 | पृष्ठ संख्या 5 |
| 2. आज 8 फरवरी 1992 | पृष्ठ संख्या 9 |
| 3. आज 21 जून 2000 | पृष्ठ संख्या 5 |
| 4. हिन्दुस्तान 7 सितम्बर 2001 | पृष्ठ संख्या 8 |
| 5. आज 9 अक्टुबर 2001 | पृष्ठ संख्या 4 |
| 6. आज 28 दिसम्बर 2000 | पृष्ठ संख्या 8 |
| 7. योजना 1-15 सितम्बर 1990 | पृष्ठ संख्या 27-29 |
| 8. नवभारत टाइम्स 27 मार्च 1993 | पृष्ठ संख्या 4 |
| 9. आज 30 मार्च 1988 | पृष्ठ संख्या 4 |
| 10. हिन्दुस्तान 5 अप्रैल 1988 | पृष्ठ संख्या 5 |
| 11. हिन्दुस्तान 16 फरवरी 1988 | पृष्ठ संख्या 5 |
| 12. दैनिक जागरण 27 अक्टुबर 2002 | पृष्ठ संख्या 8 |
| 13. आज 24 अक्टुबर 2002 | पृष्ठ संख्या 4 |
| 14. हिन्दुस्तान 11 अगस्त 1987 | पृष्ठ संख्या 5 |
| 15. पाटलीपुत्र टाइम्स 17 सितम्बर 1986 | पृष्ठ संख्या 5 |
| 16. आज 16 जून 2002 | पृष्ठ संख्या 4 |
| 17. आज 17 जून 2002 | पृष्ठ संख्या 4 |